

LOK SABHA

Thursday, March 7, 1968/
Phalguna 17, 1889 (Saka)

The Lok Sabha met at
Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

GRANTS TO BHARAT SEWAK SAMAJ

*479. SHRI JYOTIRMOY BASU: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the total amount given to the Bharat Sewak Samaj since its inception; and

(b) the value of Government land and property given to the Samaj in Delhi; and other places?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-374/68].

SHRI JYOTIRMOY BASU: This Bharat Sewak Samaj, or you might call it Bharat Experiment Samaj, is an adventure of Shri Nanda, whose conscience may rest in peace, who wanted a powerful organisation of his own to be parallel to the Congress.

SHRI S. KANDAPPAN: Parallel to the Planning Commission.

SHRI JYOTIRMOY BASU: In theory they said that it was a concern for the uplift of the people but in practice the aim was to have an industrial empire for furthering political causes. It was registered under the Societies Registration Act of 1860

although it was branded by the Government as a limb of the Planning Commission.

The Central Government alone paid over Rs. 230 lakhs without any supervision and examination of accounts. They clearly violated the provisions of the GFR, rule 149(3). The Information and Broadcasting Ministry gave Rs. 28,701 but what was publicised did not serve the Government purpose as stipulated; it served the purpose of Bharat Sewak Samaj. In West Bengal, where Shri Asoke Sen was the chief of the Bharat Sewak Samaj, he fully utilised the funds of Bharat Sewak Samaj to meet his election expenses.

MR. SPEAKER: You are giving information to the Minister. You are giving the whole history of Bharat Sewak Samaj but are not asking the question.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Under the circumstances may I ask the Minister whether any tax exemption was allowed to Bharat Sewak Samaj; if so, under what rules, what is the amount and are there any arrears?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Comprehensive consolidated accounts are not available yet; so, I am not in a position to say what concessions have been allowed to Bharat Sewak Samaj.

SHRI JYOTIRMOY BASU: But you have received the PAC Report. Do not pretend that you do not know about it.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I do not pretend at all. I am aware of the PAC Report. I only say this much that comprehensive information is not available yet.

SHRI JYOTIRMOY BASU: My second question is whether after the Public Accounts Committee suggested a ban, further grants have been given in violation of the ban by

the Ministries and the Planning Commission; if so, the details thereof and the reason for doing the same.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: After the Public Accounts Committee made its recommendation the Government of India stopped all grants and loans to the Bharat Sewak Samaj. Regarding the other aspect of the question whether the ministries have violated it, I think we have stopped all payments to Bharat Sewak Samaj. Even the Planning Commission has stopped that.

SHRI S. KANDAPPAN: The statement contradicts what the Minister says.

SHRI RANGA: I am rising only on a point of procedure. The other day you were good enough to insist that they should be prepared with information. Shri Hanumanthaiya also had some interesting remarks to make. Even today they come forward and say that have not collected the information. They do not have the audited accounts, although they have studied the report of the PAC. Is that correct?

MR. SPEAKER: I myself felt it. It is unfortunate. Last time the Minister of Social Welfare was answering the question and I said that they might kindly collect the information.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मुझे इस बात पर खेद है और मैं आप का मार्ग-दर्शन चाहता हूँ कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की 34वीं रपट में जिस के ऊपर सरकार का ऐक्शन टेकेन रपट भी कमेटी के पास आया है, यह ऐक्शन टेकेन रपट मेरे पास है, तो इस में दो तीन मंत्रालयों का संबंध है, जो गुरुपदस्वामी जवाब दे रहे हैं, मैं उनका अनादर नहीं करना चाहता हूँ लेकिन आज यह जरूरी था कि सरकार के जो प्रमुख हैं, जो प्रधान मंत्री हैं उन को यहां पर उपस्थित रह कर हमारे प्रश्नों का जवाब देतीं। मैं यह सवाल मंत्री महोदय से करना चाहता हूँ कि क्या उनका ध्यान जनरल फाइनेंशियल रूल 149 (3) की ओर गया है जिस में कहा गया है कि जिन जिन संस्थाओं को अनुदान सरकार के द्वारा दिए जायेंगे

उन के लिए यह लाजिमी है, अनिवार्य है कि वह अपना आडिटेड एकाउंट भेजें। वह नहीं भेजा गया। उस के बाद पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने साफ कह दिया है कि छः महीने के अन्दर अगर यह अपना एकाउंट नहीं भेजेंगे तो इन को भविष्य में अनुदान न दिया जाए। उस के बाद आप ने भी इस को माना था और समय दिया था और मेरे पास यह जो ऐक्शन टेकेन रपट है उस में आप ने 30 सितम्बर 1966 यह अन्तिम तारीख दी थी। इसके बाद भी सरकार के खुद के जो आश्वासन हैं और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन को तोड़ा गया है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या तत्काल आज से इस अनुदान को वह बन्द करेंगे और इन के ऊपर इनकम टैक्स लगाएंगे जैसे कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने कहा है और इस के संबंधित जितने मंत्री और अधिकारी हैं उन के खिलाफ जांच आयोग कायम करेंगे? इन तीन बातों का जवाब आना चाहिए।

छाद्य नया कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): जैसा कि अभी बताया गया, अनुदान तो सभी स्थानों से बन्द कर दिया गया है। अनुदान बन्द है

श्री मधु लिमये : कब से? कौन सी तारीख से?

श्री जगजीवन राम : तारीख हम नहीं बता सकते। देख कर बता देंगे।

श्री मधु लिमये : 30 सितम्बर 1966 मे बन्द करना चाहिए था।

श्री जगजीवन राम : वह हम देख कर के बता देंगे।

श्री कंबर लाल गुप्त : लेकिन 66-67 में अनुदान दिया हुआ है।

श्री जगजीवन राम : इसीलिए मैंने कहा कि किस तारीख से बन्द किया गया है यह

में अभी नहीं बता सकता। दिक्कत हमारी यह भी है

MR. SPEAKER: Can you tell the year, if not the date?

श्री जगजीवन राम : इसकी यह जिम्मेदारी हमारी मिनिस्ट्री को अभी पांच सात दिन पहले आई है

श्री मधु लिमये : अब देखिए, इस के लिए हम लोग क्या करें ? प्रधान मंत्री तो हैं न आप की सरकार की प्रमुख।

श्री जगजीवन राम : सुनिए, पहले मुझे कहने तो दीजिए ?

श्री मधु लिमये : सरकार की प्रमुख कहां हैं।

श्री जगजीवन राम : मैं कह रहा हूं। प्रमुख की जरूरत नहीं है। आप को समझाने के लिए हम हैं।

श्री मधु लिमये : इस में समझाने की बात नहीं है। जिम्मेदारी की बात है, आप ले रहे हैं जिम्मेदारी ?

श्री जगजीवन राम : जी हां। जिम्मेदारी के साथ ही बोल रहा हूं। मैंने इसीलिए कहा कि अभी किस तारीख से यह बन्द किया गया है, इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी कर के सदन को सूचित करूंगा

श्री हुकम चन्द्र कछवाय : जानकारी क्यों नहीं है ? इतने दिनों से सवाल पूछा जा रहा है

MR. SPEAKER: Order, order. You cannot get up like that. You must sit down. You must at least give one minute to answer the question. After that, you can ask a supplementary. You cannot interrupt like that.

श्री हुकम चन्द्र कछवाय : सवाल कितने दिनों से यह पूछा जा रहा है ? जानकारी करनी चाहिए थी।

श्री जगजीवन राम : मैंने यह कहा कि अनुदान बन्द कर दिया गया है। किस तारीख से बन्द किया गया है, यह कागज देख कर के मैं बता दूंगा। उन से सब कंसालिडेटेड एकाउन्ट मांगा गया है। कुछ उन्होंने दिया है। लेकिन जो कुछ आया है वह पूरा संतोषजनक नहीं है, इसलिए और भी उन से मांगा गया है। यह बात जरूर है

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितने वर्ष लगेंगे ?

MR. SPEAKER: Please answer the question; do not answer the interruptions.

श्री जगजीवन राम : तो यह बात सही है कि जिसकी तरफ श्री मधु लिमये ने ध्यान आकर्षित किया फाइनेंशियल रूल की तरफ कि हर साल उन का आडिटेड एकाउन्ट आना चाहिए था और उसे देखने के बाद उन्हें अनुदान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। लेकिन मैं उन सभी प्रश्नों में जा रहा हूं कि आगे क्या और कार्यवाही होनी चाहिए। इसके लिए एक कमेटी भी थी अफसरों की। वह भी सारे दास्तान में गई है। उन की कुछ सिफारिशें भी आई हैं और मैं उन सिफारिशों को देख रहा हूं कि आगे क्या कदम उठाया जाय।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था, एक का तो जवाब दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि अनुदान बन्द किया गया है, कब से, यह बता नहीं सकते, खैर, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने यह पूछा था कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की सिफारिश की रीशनी में क्या भारत सेवक समाज पर इनकम टैक्स लगाया जायेगा और जो अपराधी अधिकारी और मंत्री हैं उन के खिलाफ निष्पक्ष जांच आयोग कायम किया जायेगा ? इसका जवाब मुझे चाहिए।

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: There was a question already in the Lok Sabha on the 29th and there, we have replied that we are considering the question of setting

up an inquiry to look into all the affairs of the Bharat Sewak Samaj. It is there. We are considering it....

SHRI MADHU LIMAYE: Committee or Commission?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: As my senior colleague said, only on the 16th of last month, the administrative responsibility of the Bharat Sewak Samaj was transferred from the Planning Commission to our Ministry. Therefore, we are looking into all the affairs of the Bharat Sewak Samaj. I want to disabuse the mind of my hon. friend of this. We are not sheltering or hushing up anything at all. We are equally concerned with the state of affairs in the Bharat Sewak Samaj. As my senior colleague had put it, we are not very much satisfied with the statement of accounts that they have submitted to us, but we are still looking into it. As soon as the picture is clear....

MR. SPEAKER: What about income-tax? Is he able to say something on that?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: That is also an aspect. All these matters are relevant. We are, as I said, looking into the various aspects; there are the construction side, non-construction side, welfare and amenities activities of the Bharat Sewak Samaj—all these things are there....
(*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BASU: Stealing also....

SHRI JAGJIVAN RAM: He may be aware of it.

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने जब चीनी डीकन्ट्रोल किया, हमें तभी मालूम हो गया था ।

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I am not conversant.

As regards the other question which he raised, may I say that whatever information we have collected has already been laid on the Table of this House. The statement is available for the members.

SHRI HEM BARUA: The Public Accounts Committee submitted its report,

castigating the Bharat Sewak Samaj, to the Third Lok Sabha.....

SHRI MADHU LIMAYE: 31st March, 1965.

SHRI HEM BARUA: It was about three or four years back that the Public Accounts Committee submitted its report to the Lok Sabha. But the statement here now says after so much of time:

"In pursuance of the recommendations of the Public Accounts Committee (3rd Lok Sabha), the Samaj has been asked to furnish its consolidated accounts for every year since its inception...."

Then, This is also there:

"The question of instituting an enquiry into the affairs of the Samaj is under consideration."

There are serious charges of corruption levelled against the Bharat Sewak Samaj by a body like the Public Accounts Committee some four years back. Yet, they have been sleeping over this issue; they have done nothing. Now they tell the House that they are considering instituting an inquiry into the affairs of the Bharat Sewak Samaj. How long would they take to wake up to check the corruption in this country? That is what I want to know.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: It will not be very long. The matter has come to us just recently. There may be lapses, there may be cases of corruption, we do not know. These will form the subject-matter of inquiry. I think, very soon we will take a decision in this matter.

SHRI HEM BARUA: This is a very serious matter. The Minister says that he does not know about the corruption indulged in by the Bharat Sewak Samaj. But the Public Accounts Committee has categorically pointed that out. How long would they sleep over it like this?

MR. SPEAKER: The point is this. It has been transferred to them on the 16th of last month, but it is not a question of his Ministry alone. What has the Government done all these three years? It is not a question of Mr. Gurupadaswamy or anybody. What has the Government done?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: According to the information available to us, various attempts have been made to bring about consolidation of accounts. The Planning Commission had set up a Sub-Committee of the Co-ordination Committee on Public Cooperation and they went into the matter. They had meetings in September-October, 1966. Subsequently the Planning Commission also set up an accounts cell and they also went into the whole matter. One of the observations which both the Committees have made is that it is not possible to consolidate all the accounts because of the fact that the Bharat Sewak Samaj has maintained individual accounts for various items. They have come to this conclusion that it will be very difficult to consolidate all the accounts. But they have also said that they have got consolidated accounts for three years, from 1962 to 1965. So these are matters which are not final. (Interruptions) All that is required is being looked into.

SHRI HEM BARUA: The defence that he is trying to give us is no defence at all. We are interested in knowing this. Since Government have failed to check corruption, why is it that Government have not tried to wind up the Bharat Sewak Samaj?

SHRI JAGJIVAN RAM: As I have said, the winding up of the Bharat Sewak Samaj is not in our hands. But so far as we are concerned, our concern is not to give anything to them. As I have said already, all grants, loans or assistance to the Bharat Sewak Samaj have been stopped.

No grant has been released from November, 1966. So, for our purposes....

SHRI HEM BARUA: What about the past?

SHRI JAGJIVAN RAM: As for the past, we are looking into that matter. That is what I have said.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: I was always thinking that this Bharat Sewak Samaj was an innocent association and that it was a Samaj that is *Sama + Aja*, that is, as good as a lamb. What is the significance of transferring this Samaj to the Food Department?

SHRI JAGJIVAN RAM: No, it has been transferred to the Community Development Department.

श्री मधु लिमये : खूब समाज विकास कर रहे हैं।

श्री क० ना० तिबारी : अभी श्री मधु लिमये के प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया कि उनका आडिट भी किया जायेगा। ऐसे ही दूसरे केस हैं, जैसे महालनोबिस को 50 लाख रुपया दिया जा रहा है, ऐसी दूसरी संस्थाओं को भी दिया जा रहा है, क्या उन सब का भी आडिट किया जायेगा ?

दूसरे—ये जो कागज़ टेबिल पर रखे गये हैं, इस में लिखा है कि

“The Bharat Sewak Samaj received for its welfare and other activities grants and loans from different Ministries and other agencies of the Central Government and from the State Governments and also donations within and outside of the country.

मैं यह जानना चाहता हूँ—जब इस बात को सरकार ने तय कर लिया है कि भारत सेवक समाज को दी जानेवाली ग्रांट्स बन्द कर दी जाएंगी — तो जो सोशल एक्टिविटीज या वेलफेयर एक्टिविटीज भारत सेवक समाज कर रहा था, अब वे किस के जिम्मे होंगी और उन को कौन करेगा ?

श्री जगजीवन राम : या तो वे अपने चन्दे से कर रहे होंगे, यदि ऐसा नहीं होगा तो वह बन्द हो गया होगा।

MR SPEAKER: Shri Kanwar Lal Gupta.

SHRI JYOTIRMOY BASU: That is an utter untruth. They have taken Rs. 1 lakhs subscription.....

MR SPEAKER: Order, order. This question shall not be answered. The hon. Member cannot get up in that manner. I have called Shri Kanwar Lal Gupta.

SHRI JYOTIRMOY BASU: You cannot allow him to mislead the House.

श्री कंबर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, भारत सेवक समाज कांग्रेस का एक नान-आफिशियल विंग है और जितने अनएम्पलायड कांग्रेसी हैं, व इस में भरे हुए हैं

श्री शिव नारायण : गलत चार्ज है ।

श्री हुकूम चन्द कछवाय : बिलकुल सही है ।

MR. SPEAKER: When both these hon. Members get up, I am helpless.

श्री कंबर लाल गुप्त : इस के बार में एन्क्वायरी करने के बाद सरकार के पास यह साबूत है कि इस में एम्बेजलमेन्ट के बहुत सारे केसेज हैं । इन का जो एकाउन्ट कम्पलीट नहीं है, उसके बार में मेरी इन्फर्मेशन यह है कि खुद प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों को एकाउन्ट्स बनाने के लिये वहां भेजा गया था । मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि जब आपके पास एम्बेजलमेन्ट के केसेज हैं, जब उनके एकाउन्ट्स ठीक नहीं हैं और चारों तरफ फेवरेटिज्म और करप्शन की शिकायत है, तो यह सारा केस जिसमें करोड़ों रुपया इन्वॉल्व्ड है, आप सी० बी० आई० को देंगे ।

दूसरी बात यह है कि जैसा मन्त्री महोदय ने कहा उनको वाइन्ड-अप करने का अधिकार नहीं है लेकिन आपको यह अधिकार तो है कि उसके आडिट एकाउन्ट्स आने चाहिए और अगर नहीं आते हैं तो आप उनके ऊपर केस चला सकते हैं, सी० बी० आई० को दे सकते हैं क्योंकि यह क्रिमिनल आफेन्स है । तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सी० बी० आई० को केस देंगे ताकि वे सारी जांच करें और तबतक किसी प्रकार की भी सुविधा भारत सेवक समाज को न मिले ?

श्री जगजीवन राम : जैसा मैंने कहा, सारे मामले को देखा जा रहा है और उसके बाद जो भी मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जाएगी । जहाँ तक अनुदान का सवाल है

श्री मधु लिमये : अनुदान ही नहीं, मकान जमीन सभी चीजों की बात है ।

श्री जगजीवन राम : जैसा मैंने कहा, अनुदान तो बन्द कर ही दिया गया है इसलिए उसका सवाल ही पैदा नहीं होता ।

अब और क्या सुविधाएं मकान वगैरह की हैं वह हम देखेंगे और जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जाएगी ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : We agree that the Bharat Sewak Samaj could not render proper accounts as per rules quoted by Shri Madhu Limaye, may I know whether the Samaj has been doing social service and coming to the rescue of certain weak sections of society.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Coming to the rescue of Congressmen only.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : May I bring to the notice of the hon. Minister that in Madras the DMK Government has helped in organising a Prosperity Brigade in the State by sanctioning money to that organisation ?

SHRI S. KANDAPPAN : On a point of order. The Prosperity Brigade has nothing to do with this question. Why should he drag in a State Government here. I strongly protest. Let him confine his question to the BSS.

SHRI SEZHIAN : It is not true that government funds have been given to the Prosperity Brigade. It is true that is sustained by Government for which accounts are there. Whereas in this case the Government have allotted grants of Rs. 2 crores for the Bharat Sewak Samaj for which no accounts are maintained.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : In the Madras budget, Rs. 10 lakhs have been provided for to help the work of the Prosperity Brigade.

SHRI HEM BARUA : On a point of order. Can a State matter be raised here

MR. SPEAKER : No Comparison. That is all. The Minister cannot answer for the DMK. He was only arguing whether this is wrong. The Minister can say only about the BSS.

SHRI K. K. NAIR : How will you verify?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : The Bharat Sewak Samaj is a social service organisation. Also we have stopped grants and loans—we have made it very clear—since 1966-67. As regards the other aspect of the question, I take the information from him. We do not know whether the Government of Madras has set apart certain funds for the Prosperity Brigade.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I am asking about the social work done by the BSS.

SHRI S. KANDAPPAN : He is again and again harping on the Prosperity brigade, I am sorry about it.

SHRI H. N. MUKERJEE : It was your pinpointing the corporate responsibility of Government that led the Ministry at long last not to take shelter under the plea that they had been holding the baby only for a few months. But may I know how it is, since the Minister of Food and Agriculture admits categorically in answer to Shri Madhu Limaye's question that certain financial rules had been definitely violated, since this has gone on for a pretty long period of time and since whatever accounts have already been given do not appear to give satisfaction even to a Government which is obviously trying to shield this organisation....

SHRI JAGJIVAN RAM : No, no.

SHRI H. N. MUKERJEE : How is it that there is no definite idea about this and Government only says that it is considering the question of having an inquiry, whether it is feasible or not or something of that sort? Why does not Government positively say that an inquiry is being conducted either with CBI assistance or through whatever other agencies available?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : First of all, we must assess the state of affairs of the Bharat Sewak Samaj. Without knowing the state of affairs we cannot take

any steps. It is true that the Public Accounts Committee in their 34th report said that since the Bharat Sewak Samaj has not consolidated its accounts according to the financial rules all the grants and loans should be forthwith stopped. We have stopped the grants and loans to the Bharat Sewak Samaj since then. So we have already complied with the recommendation of the Public Accounts Committee. Regarding the other issue, we are examining it and as soon as the issues are co-ordinated and we find that an inquiry is necessary certainly we are going to do it.

SHRI H. N. MUKERJEE : Sir, I do not usually interrupt the proceedings, but here I want your protection. They are repeating over and over again, after a certain lapse of time, that they have acted in accordance with the recommendations of the Public Account Committee. I want to pinpoint a particular admission made by Shri Jagjivan Ram that financial rules have been violated. I refer to what they have said in the answer, namely, that consolidated accounts which the Samaj is said to have given were found to be unsatisfactory and this has gone on for a period of time. My question was in relation to that and not in regard to what they have done in regard to the recommendations of the PAC. Why do they not say, we are having an inquiry; why do they say we are considering having an inquiry about this scandalous affairs?

SHRI JAGJIVAN RAM : It has been already explained that after the report of the Public Accounts Committee a Committee of officials went into the details of the accounts submitted by the Bharat Sewak Samaj. The Samaj had submitted some sort of consolidated accounts. As I have said, the accounts so far submitted are not satisfactory in all respects. But the matter is being pursued. I have no doubt that further inquiry will be necessary in the matter. As I have already assured the House, as soon as the picture is clear, (*Interruption*) as soon as I have gone into the case, appropriate action whatever it may be of the two or three alternatives suggested—will be taken.

SHRI RANDHIR SINGH : May I ask the hon. Minister, through you, Sir whether it is not a fact that the Bharat

Sewak Samaj is doing extremely fine work in the rural areas in building roads, running schools and hospitals etc., and is it not fact that 95 per cent of its employees and office-bearers are non-Congress people?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : It is a fact that the Bharat Sewak Samaj is doing a lot of welfare and amenities work and has given employment to a large number of people.

SOME HON. MEMBERS rose—

MR. SPEAKER : Order, order. All hon. Members may resume their seats. We have already spent half an hour on this. The hon. Minister has given all the information he has in his possession at present and perhaps he would not be able to give more information now. We can have a half-an-hour discussion or a one-hour discussion at some other time. I have no objection to call another half-a dozen Members and take the full Question Hour for this, but I do not think the hon. Minister will be in a position to give any further information at present.

श्री मधु लिमये : इस से काम नहीं चलेगा । यह तो प्रीविलेज का मामला है । मैं ने विशेषाधिकार भंग, प्रीविलेज का नोटिस दे दिया है । यह कोई आधे घंटे की बात थोड़े ही है ।

MR. SPEAKER : I do not mind spending this whole hour on this question, but then the one hour would be over and there cannot be any further discussion on this.

श्री सु० अ० खां : इसके अलावा आज की लिस्ट में और भी तो बहुत से महत्वपूर्ण सवाल आने को हैं और जो आप के इस मौजूदा क्वेश्चन को ही आगे चलाने जा रहे हैं तो उन का क्या होगा ? दूसरे आप इस के लिए अलग डिस्कशन का टाइम भी तो देने जा रहे हैं ।

SHRI RANGA : Sir, I can only refer to all the questions that have been put and the replies given. In the light of all that and the last reply given by the hon. Minister, may I suggest to him and also enquire as to what is it that stands in their way in agreeing with the suggestion that has already been made by several hon. Members here in

the light of not one report but repeated reports from the Public Accounts Committee expressing dissatisfaction with the way in which funds have been used or misused by the Bharat Sewak Samaj? What is it that stands in their way in agreeing to appoint a Commission of Inquiry or Committee of Inquiry so that all the information would be placed before them? That is my plea with them. May I also add that in view of the fact that Government has taken the right decision in stopping all grants since 1966, would it be pleased now to advise all the State Governments also to take similar action in view of the fact that State Governments also have been making grants to this organisation?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : My information is that the State Governments also have stopped all the grants and loans. We have already stopped it in the year, 1965 and 66.

SHRI S. M. BANERJEE : Why do you not declare it illegal?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : About the other question as to what stands in the way of setting up an inquiry immediately, the only thing that is standing in our way is that we are studying all the papers that have been transferred from the Planning Commission to our Ministry. Only on the 16th of last month this responsibility was thrown on us. Therefore, we are considering all the aspects and if the situation warrant certainly we will have it. It is in our consideration whether we should set up an inquiry committee or not.

SOME HON. MEMBERS rose—

MR. SPEAKER : Let us go to the next question.

श्री गुणानन्द ठाकुर : आधे घंटे से यहां मैं बैठा हुआ हूं और बारबार उठने पर भी मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई । इस तरीके से नये सदस्यों की अध्यक्ष महोदय अवहेलना करते हैं तो मैं प्रोटैस्ट के तौर पर वाक्आउट करता हूं ।

Shri Gunanand Thakur then left the House.